2019 की सोलर नीति के अनुसार ही व्यवसायियों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में राहत दें : हाईकोर्ट

अदालत ने राज्य सरकार तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवसायियों ने 2019 की नीति के तहत ही छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिये निवेश किया था

- **जैसा कि विदित है कि इस नीति के तहत व्यवसायियों को सात साल तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने से राहत दी गई थी परंतु राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरूद्ध जाते हुए व्यवसायियों से ड्यूटी वसूल रही थी और इसके एवज में बिल भी जारी कर रही थी**
- **हाईकोर्ट ने ड्यूटी वसूले जाने पर अंतरिम रोक लगाई है और कंपनियों के खिलाफ कोई भी उत्पीड़क कार्यवाही करने पर भी रोक लगाई**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने इमारतों की छत पर (रूफ टॉप) सोलर पैनल लगाकर व्यवसायिक उपयोग के लिये बिजली उत्पादन करने से जुड़ी कंपनी इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को राहत देते हुए आदेश दिये हैं कि राज्य सरकार अपनी 2019 की सोलर नीति के अनुसार इस कंपनी से बिजली उत्पादन के लिये इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना वसूलें और ना ही कोई अवपीड़क कार्यवाही ना करें।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश 20 अक्टूबर को दिये थे जिसकी आदेश की प्रतिलिपि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की ओर से एडवोकेट अनंत कासलीवाल और उनके सहायक वकील वैभव कासलीवाल और शशांक कासलीवाल पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि 2019 में राज्य सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी जारी की थी जिसकी धारा 16.4 के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों पर आने वाले सात वर्ष तक राजस्थान सरकार और जयपुर विद्युत वितरण निगम इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। परंतु अपनी ही नीति के विरूद्ध जयपुर विद्युत वितरण निगम कई बिजली उत्पादकों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल रही थी और बिल भी जारी कर रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने छत पर सोलर प्लांट के नये प्रोजेक्ट के लिये यह छूट हटा दी है।

परंतु हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे कई मामले दायर किये गये जिनमें कंपनियों ने 2019 की नीति के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाये थे। इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार नये आने वाले प्रोजेक्टों के लिये तो छूट हटा सकती है पर जो 2019 की नीति के तहत ये लगाये गये हैं उन पर यह छूट लागू रहेगी। ऐसा ही एक याचिका एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी जिसमें सीनियर अधिवक्ता संदीप जौहरी और उनके सहायक अधिवक्ता शुभंकर जौहरी पैरवी के लिये पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकती और इन कंपनियों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नही वसूल सकती।

राजस्थान सोलर एसोसियेशन ने भी इस वर्ष हाईकोर्ट के समक्ष सरकार की 2019 की नीति के विरूद्ध इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूले जाने के कई मामले दर्ज किये गये थे। जिनमें हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट ने एपीएम इंडस्ट्रीज राहत देते हुए उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर अंतरिम रोक लगाई थी। इन मामलों की तर्ज पर हाईकोर्ट ने इमामी एग्रोटेक को भी राहत दी है और उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर भी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लाहौल स्पीति में कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया।

मंगलवार को चन्द्रग्रहण के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में तीव्र हवाओं के साथ बारिश होने लगी जो देर रात तक रूक-रूक कर चलती रही। इससे शहर में सर्दी बढ़ने से लोग गर्म कपड़े पहने नजर आये।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत

जयपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ब्राहमण समाज राजस्थान ने स्वागत किया है। प्रदेशाध्यक्ष अंबिका प्रकाश पाठक ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने केन्द्र की मोदी सरकार के उस फैसलें पर मोहर लगा दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया था। इस निर्णय के खिलाफ कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन जीत आखिरकार सत्य की हुई और गरीब व कमजोर सवर्ण को भी संबल मिला है। इस आरक्षण पाने के लिये लगभग दो दशकों तक संघर्ष किया और केन्द्र सरकार ने आरक्षण से वंचित सवर्ण जातियों को भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण दिया।

प्रदेश में 31 नए करोना संक्रमित मिले मंगलवार को

जोधपुर में सर्वाधिक 6 नए मरीज सामने आए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में फिर वृद्धि हुई है। इस दौरान मंगलवार को 31 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 18 रोगियों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले सात दिनों से करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 10 जिलों में 31 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 23 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा 6 नए संक्रमित जोधपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा पाली में 5, जयपुर व अलवर में 4-4, बीकानेर व सीकर में 3-3, प्रतापगढ़ और अजमेर में 2-2 तथा भरतपुर और सवाई माधोपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 5708 जांचे की गई।

- **राज्य में फिर रिकवरी में कमी आने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं।**

प्रदेश में मंगलवार को केवल 18 ही संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही फिर एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में कोई भी मरीज रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 106 हो गए हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9646 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को गोपालपुरा, कोटपूतली, मालवीय नगर और मानसरोवर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा : कश्मीरी लाल

- **स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह**

जयपुर। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कश्मीरी लाल स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक को राजापार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जागृत होने से देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है। संघ की प्रेरणा से चल रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से देश के युवाओं में एक नई चेतना जागृत हुई है। उसी का परिणाम है कि अब युवा सरकारी नौकरी के बजाय स्वयं का रोजगार शुरू कर लोगों को नए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि देश में आज स्वदेशी, स्वरोजगार व स्वावलंबन का भाव उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉ शैलेंद्र ने कहा कि आज स्वदेशी का स्वावलंबन अभियान पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और अब लोग वस्तुओं को खरीदने से पहले स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का आंकलन करने लगे हैं। मंच के प्रांत संयोजक देवेंद्र भारद्वाज ने प्रांत कार्यकारिणी में राजेश शर्मा को कोष प्रमुख एवं धर्मेंद्र शर्मा को सह संपर्क प्रमुख के पद पर नियुक्त किया साथ ही स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा उद्यमियों को मंच पर बुलाकर स्वदेशी का दुपट्टा देकर सम्मानित कराया और उनके स्टार्टअप्स को राष्ट्र की उन्नित में अधिक भागीदारी निभाने की शुभकामनाएं देकर उनका उत्साहवर्धन किया। महिला कार्य प्रमुख अर्चना मीणा ने स्वावलंबी भारत अभियान के डिजिटल प्लेटफार्म माय एसबीए में अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का आव्हान किया। मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार डॉ धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि स्वरोजगार करने वाले युवाओं की छोटी-छोटी कहानियां भी प्रेरणा के रूप में समाज के बीच लाई जानी चाहिए। मंच के क्षेत्र संयोजक डॉ.सतीश आचार्य ने कहा कि स्वदेशी को लेकर देशभर में एक सकारात्मक व अनुकूल माहौल का निर्माण हुआ है। प्रांत प्रचार प्रमुख डा धर्मवीर चंदेल ने बताया कि इस अवसर पर प्रांत संगठक मनोहर शरण का स्थानांतरण गुजरात होने पर उन्हें सभी कार्यकर्ताओं ने भावभीनी विदाई दी।

बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी

जयपुर। शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से पेश कुल 28 अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है। लिखित बहस के बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है।

धर्मांतरण का राज्य सरकार को संरक्षण : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में धर्मांतरण के मामले पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान कितना असुरक्षित है, इसका नमूना धर्मान्तरण है, राज्य में लव जेहाद और लैण्ड जेहाद की घटनाएं होती रही हैं, आवाज उठाने पर धर्मान्तरण थोड़े दिन के लिये रुका था, लेकिन अब फिर से हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोती रही, कमज़ोर लोगों को सुनियोजित तरीके से टार्गेट किया जाता है, धर्मांतरण के मामलों में भोले, आर्थिक कमजोर और निर्बल लोगों को टार्गेट कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मन्त्री भी हैं और उनकी नाक के नीचे यह हो रहा। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्मांतरण को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस की तुष्टिकरण और वोट बैंक की सियासत के तार भी इससे जुड़े हो सकते हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।

कॉलेज शिक्षा आयुक्त बताए क्यों नहीं की आदेश की पालना?

- **हाईकोर्ट के आदेश के वाबजूद निजी कॉलेज को स्थाई एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज को सत्र 2020-21 की स्थाई एनओसी जारी करने के अदालती आदेश के बावजूद एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त को 28 नवंबर को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि आदेश की पालना हो जाती है तो कॉलेज आयुक्त को पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश जामिया मदरसा एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आत्माराम मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज शिक्षा विभाग में वर्ष-2020-21 की स्थाई एनओसी के लिए आवेदन किया था। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जिस पर गत वर्ष 2 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एक माह में एनओसी जारी करे। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब 11 माह बीतने के बाद भी विभाग ने अब तक एनओसी जारी नहीं की है।

ऐसे में अदालती आदेश की पालना कराई जाए और अवमानना कर्ता अफसरों को दंडित किया जाए। वहीं याचिका में जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने 28 नवंबर तक आदेश की पालना नहीं होने पर कॉलेज शिक्षा आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

कांग्रेस के मंत्री-विधायक ग्रेटर निगम के पार्षदों को साधने में जुटे, उधर हैरिटेज के पार्षद बगावत पर उतरे

मेयर मुनेश की कार्यशैली से नाराज करीब एक दर्जन कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने हैरिटेज निगम में धरना दिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम में 10 नवंबर को महापौर उपचुनाव है, ऐसे में मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस का मेयर बैठाने के लिए इन दिनों कांग्रेस के मंत्री-विधायक जमकर जोड़तोड़ की कोशिशों में जुटे हैं। बाड़ेबंदी में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों से इन दिनों समझाइश और मान-मनुहार का दौर चल रहा है। ताकि क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति नहीं बने।

वहीं दूसरी ओर हैरिटेज नगर निगम में मंगलवार को एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस की महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निगम मुख्यालय पर करीब एक घंटे तक धरना देकर विरोध भी जताया। इनकी नाराजगी थी कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हैरिटेज निगम में बीते 2 साल से ना तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जा रही है और न ही संचालन समितियां बनाई गई। वार्डों में विकास कार्यों और सफाई कर्मचारियों को लेकर भी सुनवाई नहीं होती।

उधर मंगलवार को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बगरू विधायक गंगा देवी के साथ-साथ विद्याधर नगर के कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल, सांगानेर से पुष्पेन्द्र भारद्वाज और मालवीय नगर से विधायक प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा ने ग्रेटर निगम क्षेत्र के पार्षदों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि भाजपा में मेयर प्रत्याशी को लेकर चल रहे असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में कांग्रेस नेता जुटे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा ने सुखप्रीत बंसल का नाम ऐन वक्त पर काटा और कार्यवाहक शील धाबाई को भी मेयर प्रत्याशी बनाने से पार्टी ने परहेज किया, इसे लेकर समर्थक पार्षदों और कई बड़े नेताओं में नाराजगी तो हैं।

- **धरने पर बैठे कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों की नाराजगी थी कि दो साल के कार्यकाल में मेयर मुनेश गुर्जर बोर्ड मीटिंग तक नहीं बुला रही है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते। उधर कांग्रेस सरकार संचालन समितियां गठित नहीं कर रही है।**
- **इन पार्षदों ने मेयर मुनेश को फोन पर चेतावनी दी है कि अगर 15 नवंबर तक उनकी मांगों पर सुनवाई न हुई तो पुनः धरना देंगे**

हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सभी एकजुट हैं और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा पार्षद रश्मि सैनी को महापौर बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर क्रॉस वोटिंग की संभावना बनती है तो कांग्रेस इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए कांग्रेस के मंत्री-विधायक और विधायक प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र के पार्षदों से बातचीत करने में जुटे हैं।

उधर मंगलवार दोपहर को जिस तरह से कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने हैरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसे लेकर भी मंत्री-विधायक चिंतित है। मंगलवार को जब करीब 19 पार्षद हैरिटेज नगर निगम में बीते दो साल से बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाये जाने और संचालन समितियां गठित न होने को लेकर धरना देने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। हालांकि गुरूनानक जयंती का अवकाश होने के कारण निगम मुख्यालय में छुट्टी का माहौल था। धरने पर बैठे पार्षद कांग्रेस की सरकार, विधायक और मेयर को कोसते दिखे।

इन पार्षदों का कहना था कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार है और हैरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है, उसके बावजूद कांग्रेस के ही पार्षदों में विकास कार्य नहीं हो रहे। अफसर उनके फोन तक नहीं उठाते है। कांग्रेस बोर्ड को समर्थन दे रहे निर्दलीय पार्षदों ने भी कमेटियां बनाने की मांग की। पार्षदों ने महापौर मुनेश गुर्जर को मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर अपनी मांगे रखी। बैठक से पार्षदों ने कमेटियां गठन करने, विकास कार्यो की स्वीकृत, सफाई कर्मचारियों के समानीकरण और बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की।

पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त उनके विकास कार्यो की फाइलों को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। पार्षदों ने चेताया है कि अगर 15 नवंबर तक उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठेंगे। धरने पर बैठने वाले इन पार्षदों में जाहिद निर्माण, मौजम बानो, मोहम्मद एहसान, सलमान मंसूरी, सना वसीम खान, जमीला बेगम, मोहम्म्द फारूख, आयशा सिद्धकी, रोहित कुमार, मोहम्मद जकरिया शेरम, अरविंद मेठी, शोएब मुबारक, सोहेल मंसूरी, संतोष, नरेश नागर, उमरदराज, मोहम्मद शफीक, अकबरुद्दीन और सुनीता देवी शामिल थे।

मुख्य सचिव सहित अन्य को अवमानना नोटिस

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक की लंबित विभागीय जांच के संबंध में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षाधिकारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश ममता की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत नौ मार्च को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय जांच को छह माह में निस्तारित किया जाए। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संशोधित आरोप पत्र पुन: जारी कर दिया और विभागीय कार्रवाई जारी कर रखी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को विभागीय अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता की विभागीय जांच को निस्तारित किया जाए और अदालत अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई करे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

गुरु नानक देव ने सम्पूर्ण मानवता को भाईचारे का संदेश दिया : राज्यपाल

गुरू नानक जयन्ती के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजा पार्क गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कीर्तन में भाग लिया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर मंगलवार को राजा पार्क गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दिवान आयोजन में भाग लिया।

राज्यपाल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पूरे देश में घूम-घूम कर भाईचारे एवं प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। हमें उनके संदेशों के अनुसार अपने आचरण एवं व्यवहार को ढालते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, विधायक सतीश पूनिया, कालीचरण सराफ, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबी एवं अनुयायी उपस्थित रहे।

आमेर में पैदल मार्च आज

जयपुर। देश और दुनिया में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों के निर्माण और पीने के पानी की सप्लाई माँग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में आमेर तहसील का 9 नवंबर को घेराव कर गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। भाजपा, आमेर शहर मंडल द्वारा आयोजित पैदल मार्च कल 9 नवंबर को कुंडा तिराहे से आमेर तहसील तक निकाला जायेगा।

युवाओं ने मिश्र से भेंट की

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र से मंगलवार को राजभवन में भारत को जानें कार्यक्रम के तहत 14 देशों से आए विदेशों में रह रहे भारतीय युवा प्रतिभागियों ने मुलाकात की।